21 वीं शताब्दी में भारत-अमेरिका सामरिक संबंध

[1]Tej Pratap Singh, [2]Dr. Amarjeet Kumar Singh

[1]Research Scholar, [2]Professor
[1]Apsu Rewa
[2]Government Girls P.G. college Rewa M.P.

संक्षेप: 21वीं सदी में भारत अमेरिका के सामरिक संबंध में अत्यधिक प्रगति हुई है और यह वर्तमान में अन्य संबंधों का आधार बन गया है इन संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत की आर्थिक क्षमता बदली हुई क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियां जिसमें दक्षिण एशिया में बढ़ते हुए चीन के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने कि भारत और अमेरिका दोनों के शामिल। सामरिक संबंधों को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और उनके पश्चात राष्ट्रपति बुश ने गति दी, जिसे राष्ट्रपति ओबामा ने शिखर पर पहुंचा दिया और जिसे उनके उत्तराधिकारियों ने भी सामरिक संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया जिससे दोनों के सामरिक संबंध निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।

शब्दावली: सामरिक, आर्थिक उदारीकरण, शीत युद्ध

परिचय :

शीत युद्ध के दौर में परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों के कारण, भारत और अमेरिका के मध्य सामरिक संबंधों की शुरुआत नहीं हो पाई। शीत युद्ध के बाद बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों और राष्ट्हितों में समानता के कारण भारत और अमेरिका के मध्य सामरिक संबंधों की शुरुआत 1990 से ही प्रारंभ हो गई जब अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भारत के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई। उसके पश्चात भारत ने निरंतर अमेरिका से बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया यद्यपि यह संबंध 21वीं सदी में ही बेहतर हो सके, जिसके कारण थे, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक क्षमता एवं विशाल बाजार, दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, भारत की बढ़ती हुई सूचना प्रौद्योगिकी में क्षमता जैसे कारकों ने भारत-अमेरिका सामरिक संबंधों को मजबूत किया। इस शोध पत्र का उद्देश्य 21 वी शताब्दी में भारत अमेरिका के मध्य आए सामरिक संबंधों में सुधार के कारकों का परीक्षण एवं इस दौरान किए गए महत्वपूर्ण समझौतों के महत्व का विश्लेषण करना है।

21 वीं शताब्दी में सामरिक संबंध:

शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका संबंध अच्छे नहीं रहे। शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन आने से और भारतीय विदेश नीति मैं उस परिवर्तन के अनुरूप अपनी नीतियों में समायोजन से भारत अमेरिकी संबंधों में सुधार होना प्रारंभ हुआ। भारत ने अपनी आर्थिक और सामरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था में खुलापन लाने के लिए आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई और सामरिक सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। अमेरिका ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भारत को मदद दिला कर संबंधों को आगे बढ़ाया। 1 इसी कड़ी में सैन्य क्षेत्र में सहयोग के लिए अमेरिका और भारत ने मिलकर 1992 में मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। 1998 में भारत के द्वारा पपरमाणु परीक्षण करने से संबंधों में जो नरमी आई थी वह कुछ समय के लिए कम हो गई। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। यद्यपि इन प्रतिबंधों का कोई ज्यादा असर भारत पर नहीं हुआ बल्कि इससे अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देशों को ही आर्थिक हानि हुई। 2

2000 के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया। दोनों देशों के आपसी संबंध अभूतपूर्व ढंग से घनिष्ठ होना प्रारंभ हो गए, जब मार्च 2000 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों

के बाद दोनों देशों के बीच बदली परिस्थितियों में फिर से संबंध मजबूत होने लगे। भारत जहां विश्व की एकमात्र शक्ति अमेरिका से संबंध सुधारने का इच्छुक है,वहीं भारत आर्थिक दृष्टि से एक उभरता हुआ देश होने के साथ-साथ एक बहुत बड़ा बाजार भी है। अमेरिका चीन की आर्थिक और सैनिक शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत को दक्षिण एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है। जनवरी 2002 में भारत ने अमेरिका के साथ 'जनरल सिक्योरिटी ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किया इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश हथियारों के किसी सौदे में वर्गीकृत तकनीकी रक्षा संबंधी सूचनाओं की अदला-बदली करेंगे तथा एक दूसरे की खुफिया प्रौद्योगिकी सूचनाओं की रक्षा करेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापक तकनीकी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। 3

जनवरी 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने अमेरिका की यात्रा की इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने एन एस एस पी पर हस्ताक्षर किए यह सहयोग सामरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें चार क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमत बनी थी - दोहरे उपयोग की तकनीक, मिसाइल रक्षा, नागरिक परमाणु सहयोग, और शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग। परिणामस्वरूप अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इसरो को अपनी प्रतिबंधित सूची से हटा दिया। जिससे सहयोग और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। जुलाई 2005 भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के मध्य एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। जिसका भारत और अमेरिका संबंध पर एक दूरगामी प्रभाव पड़ा। 4 दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दे दी। यह समझौता कई दौर की वार्ताओं और दोनों देशों की आंतरिक राजनीतिक कठिनाइयों के बावजूद 2008 में संपन्न हुआ। दोनों के मधुर होते संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि दोनों देशों ने लंबी वार्ता तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने में सफलता प्राप्त की। 5

वर्ष 2006 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश भारत यात्रा पर आए और भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बताया। वर्ष 2008 भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा। सिविल न्यूक्लियर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसकी घोषणा जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई थी। गौरतलब है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक विशेष सुरक्षा समझौता किया। इससे दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हुए, आर्थिक और उच्च तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर खुले हैं। परमाणु समझौते के बाद अमेरिका ने भारत को परमाणु शक्ति मान लिया। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। भारत अमेरिका परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते की बुनियाद 2005 में वॉशिंगटन में पड़ी थी। इस समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अमेरिका को अपने घरेलू कानून में बदलाव करना पड़ा जिसे 123 एग्रीमेंट कहते हैं। इन कानूनों के मुताबिक भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सहयोग के लिए अमेरिका ने छूट दे दी थी, जिसमें प्रमुख था भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से मुक्त कर देना॥ इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत का बहिष्कार समाप्त कर दिया।

बराक ओबामा 20 जनवरी 2009 से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ओबामा के राष्ट्रपति बनने से भारत - अमेरिका संबंध में एक नया आयाम आया । संबंधों में गर्मजोशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओबामा अपने कार्यकाल के दौरान दो बार भारत आए। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार के बाद ओबामा सरकार ने भारत के साथ सामरिक संबंध को और आगे बढ़ाया और 2016 में हुआ अभूतपूर्व रक्षा समझौता लेमोए, जो दोनों देशों के बीच मील का पत्थर साबित होने वाला है। शीत युद्ध के कटु अनुभव के बाद सही मायने में ओबामा के दौर में ही भारत और अमेरिका संबंध शिखर पर पहुंचे। लेमोए समझौते से दोनों देश एक दूसरे किशन सुविधाओं का उपयोग अब कर सकते थे। भारत को एमटीसीआर की सदस्यता दिलाने में ओबामा ने अहम योगदान दिया। भारत को एनएसजी में प्रवेश दिलाने के लिए भी प्रयास किया। राष्ट्रपति ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया। बराक ओबामा आतंकवाद के खात्मे की वकालत करते रहे। पीएम मोदी के आतंकवाद पर कड़े रुख का समर्थन करते रहे, और दोनों नेताओं ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया ।ओबामा ने इस्लामिक स्टेटस सहित पश्चिम एशिया के कई आतंकी संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की।

लेमोए समझौता

लेमोए समझौता सितंबर 2016 में भारत - अमेरिका के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता है। यह दोनों देशों के मध्य सामरिक सहयोग को दूरगामी परिणाम देने वाला है। इस समझौते से दोनों देश मरम्मत और आपूर्ति के लिए एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। विशेष रूप से एक-दूसरे के वायु सेना का प्रयोग भी युद्ध के दौरान कर सकेंगे इस संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को मुख्य सहयोगी का दर्जा दिया है अमेरिका रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत का सहयोग बढ़ाएगा विगत 50 साल के इतिहास में यह बड़ा बदलाव है। 6

कॉमकासा समझौता

भारत ने अमेरिका के साथ 2018 में कॉमकासा समझौता किया किया। यह समझौता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। समझौते से अब अमेरिका अपनी संवेदनशील सुरक्षा तकनीकों को भी भारत को भेज सकेगा। भारत पहला ऐसा गैर नाटो देश है जिसे अमेरिका ने यह सुविधा प्रदान की है। भारत और अमेरिका में यह समझौता होने के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के ज्यादा करीब आएंगी और उनमें सहयोग बढ़ेगा। कॉमकासा महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है, जो अमेरिका अपने सहयोगी और गरीबी देशों के साथ करता है, जिससे सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ सके। इसके तहत भारतीय सेना को अमेरिका से महत्वपूर्ण और कूट रूप से सुरक्षित या गोपनीय रक्षा प्रौद्योगिकी मिलेंगी। यह समझौता अमेरिका से मंगाए गए रक्षा प्लेटफॉर्म पर उच्च सुरक्षा वाले संचार उपकरणों को लगाने की भी इजाजत देता है। इसके तहत भारत को अपनी सेना के लिए अमेरिका से कुछ आधुनिक संचार प्रणाली मिलने की अनुमति मिल गई है। इन प्लेटफार्म में c- 17 ग्लोबमास्टर और p8i एयरक्राफ्ट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर प्रमुख हैं। अब भारत अमेरिका की आधारभूत संरचनाओं का इस्तेमाल कर सकेगा। भारत अमेरिका से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी हासिल कर सकेगा और अमेरिका तथा भारतीय सशस्त्र बलों के बीच अंत:क्रिया सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क तक भारत की पहुंच होगी। 7

भारत पहले ही अमेरिका के साथ 4 में से 2 समझौते कर चुका है 2002 में जनरल सिक्योरिटी आफ इनफॉरमेशन एग्रीमेंट और 2016 में लाजिट्क्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। कानूनी तौर पर अमेरिका से आधुनिक हथियार मिल सकेंगे।

टू प्लस टू डायलॉग

टू प्लस टू डायलॉग दो देशों के बीच रणनीतिक और सैन्य स्तर पर काफी करीबी तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर परस्पर सहयोग का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में शुरू की गई भारत अमेरिका के बीच टू प्लस टू डायलॉग ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत की जगह ली जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि थी। ओबामा प्रशासन ने कारोबार, नौकरिया बढ़ाने, निवेश माहौल को सुधारने, और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य साधने के लिए भारत अमेरिका स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल डायलॉग सिस्टम बनाया था। भारत अमेरिका के बीच टू प्लस टू डायलॉग 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में हुई भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेशी सुषमा स्वराज ने और अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री माइक और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने हिस्सा लिया था। पहली बैठक में ही कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था 'कॉमकासा' का समझौता इसके अतिरिक्त ईरान से कच्चे तेल की खरीद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई थी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत बनी वही दूसरा टू प्लस टू डायलॉग 19 दिसंबर 2019 को हुई एवं तीसरी बातचीत जो कि 27 अक्टूबर 2020 को हुई में 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट' पर समझौता हुआ। 8

टू प्लस टू डायलॉग में सुरक्षा संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसका मकसद भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी के लिए सकारात्मक माहौल और बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना है इससे दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि के साथ-साथ शीर्ष प्राथमिकताओं को बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा जाना सुनिश्चित होता है।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जिनमें काफी समानताएं हैं भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिका को भारत का बाजार चाहिए लेकिन अब भारत भी बराबरी के मंच पर है। अब यह अच्छी तरह से ही साबित हो चुका है की दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए काफी कुछ है। वर्तमान में भारत - अमेरिका सामरिक संबंध बराक ओबामा के कार्यकाल में शिखर पर पहुंचे। उन्हीं के कार्यकाल में आपसी संबंध वैश्विक सामरिक भागीदार के रूप में विकसित हुए जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया। इससे यह पता लगता है कि आज भारत और अमेरिका की एक दूसरे पर निर्भरता किस हद तक है जहां देखो वहां खड़े दिखाई दे जाते हैं चाहे वह अंतरिक्ष क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो या तकनीकी। इस प्रकार और भी कई क्षेत्र हैं जो भारत अमेरिका की पारस्परिक निर्भरता को इशारा करते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज समान धरातल पर बन रहे भारत अमेरिका संबंध मजबूती और परिपक्वता का प्रतीक है और भारत-अमेरिका भविष्य में भी ना केवल पारस्परिक हितों के लिए साथ चलेंगे बल्कि जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद जैसे संवेदनशील वैश्विक मुद्दों से उत्पन्न हुए वैश्विक अशांति को समाप्त करने और विश्व में शांति एवं प्रगति का माहौल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भागीदार साबित होंगें।

संदर्भः

1. आजम, जे. कौशर, 'डिसकोर्स इन ट्रस्ट यूएस साउथ एशिया रिलेशन', साउथ एशियन पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1999, पृ. 170
2. मटटो, अमिताभ, इंडियाज न्यूक्लियर डिफरेंट: पोखरण 2 एंड बियोंड, न्यू दिल्ली, हर आनंद, 1999, पृ. 66
3. कपूर, अशोक, के.के. मलिक, इंडिया एंड द लिमिटेड स्टेटस इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, सेज पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2002, पृ. 167
4. शुक्ला, वात्सल्य, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द न्यू मिलेनियम, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स, न्यू दिल्ली, 2005, पृ. 122
5. तन्वी, मदन, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेटस: विल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इमर्ज?, प्रेजेंटेशन एट द हडसन इंस्टिट्यूट, वाशिंगटन डीसी, 4, सितंबर, 2014
6. लिमय, सत्तू, यूएस इंडिया रिलेशंस: प्रोग्रेस ऑन डिफेन्स व्हाइलस इकोनॉमिक इश्यू लेग, कंपैरेटिव कनेक्शन्स, वॉल्यूम 18, नं. 2, सितंबर, 2016, पृष्ठ 54
7. डेविड, रिट्ज, हास सेज यूएस इंगेज्ड इन अन्डीकेशन ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, सीएनएन, 3 जनवरी, 2018
8. मुखर्जी रोहन, चाओस ऐस अपॉर्चुनिटी: द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर इन इंडिया ग्रैंड स्टेटजी, कंटेंपरेरी पॉलिटिक्स, वॉल्यूम 26, नंबर 4, 2020, पृष्ठ 420 - 435